DELHI POLICE 2025

CONSTABLE HCM AWO/TPO DRIVER

यकीन बैच

POLITY

भारत के संवैधानिक विकास

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF INDIA Part -3

09-04-2025 12:05 PM

Polity → भारत का संवैधानिक विकास [Constitutional development of India.]

पिट्स इण्डिया एक्ट-1784 [Pitt's India act-1784]

Act of settlement -1781 की असफलता के बाद Pitt's India act-1784 आया

(i) इस अधिनियम/act → कम्पनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र / occupied Indian Territory by company) → अब ब्रिटिश ताज / British crown के नियन्त्रण में आये → इन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत / British India.

(ii) इस अधिनियम द्वारा :- व्यापारिक / Business एवं राजनीतिक [Political] कार्य अलग किये

- व्यापारिक / Business → नियन्त्रण / Control → Board of directors [निदेशक मण्डल]
- राजनीतिक [Political] → नियन्त्रण / Control → [Board of Control] → नियन्त्रक मण्डल — कुल सदस्य / Total members 6 ✓

③ Board of Control [नियन्त्रक मण्डल] → 6 सदस्य

- 1 → Chancellor of Exchequer [चांसलर ऑफ़ एक्सचेकर]
- 1 - राज्य सचिव / State secretory
- 4 - प्रिवी काउंसिल के सदस्य [Member of Privy Council]

④ गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से ③ कर दिया गया

⑤ प्रान्तीय परिषद (Provincial Council) के सदस्य भी 4 से 3 कर दिये।

⑥ गवर्नर जनरल को अधिकार दिया यदि प्रान्तीय सरकारें (Provincial government) केन्द्रीय शासन [central Rule] न मानने पर उन्हें बरखास्त / suspend) किया सकता था।

⑦ कम्पनी के डायरेक्टर्स / Directors of Company) की बिना स्वीकृति / Permission के भारतीय रियासतों से गवर्नर जनरल न तो युद्ध / war एवं न ही सन्धि / Treaty करेगा।

⇒ 1793 का राजलेख [Charter act 1793]

(1) इस अधिनियम द्वारा कम्पनी के अधिकारों [Rights of Company] को 20 years के (बढ़ाया) Extened कर दिया

(2) इस अधिनियम द्वारा [Board of Control] नियन्त्रक मण्डल के सदस्यों को वेतन/Salary भारतीय राजस्व [Indian Revenue] से दी जायेगी।

⇒ 1813 का राजलेख [Charter act of 1813]

(1) कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार [trade monopoly] को समाप्त कर दिया

[Note:- कम्पनी चीन साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार करती रहेगी।]

(2) अंग्रेज [Britishers] भारत में व्यापार कर सकते है।

③ ब्रिटिश सरकार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख/वर्ष खर्च करेगी
British Government will spend 1 Lakh/year to the Educatim of Indians

④ ईशाई धर्म के प्रचार की स्वतन्त्रता मिली

⇒ 1833 का राजलेख / Charter act of 1833 :—

- कम्पनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार (All trade monopoly) समाप्त कर दिया।
- बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया
  - Last → विलियम बैंटिक
  - प्रथम → (विलियम बैंटिक)
- कम्पनी के अधिकारों को पुनः (again) 20 वर्षों के बढ़ाया / Extened किया
- गवर्नर जनरल की परिषद (Council of Governor-General) में चौथे सदस्य / 4th member के रूप में विधि सदस्य / Law member जोड़ा गया।
- प्रथम विधि आयोग / 1st Law Commission → 1834 → 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य
  - प्रथम अध्यक्ष → मैकाले
- 1843 दास प्रथा पर रोक लगा।